PRESS RELEASE

June 01, 2020

Statement by Randeep Singh Surjewala, Incharge Communications, AICC

Brazen Chinese transgressions into Indian Territory as Modi Govt silent!

There can be no compromise with India's "Security and Territorial Integrity".

Umpteen news reports reflect that Chinese forces have made serious transgressions into Indian Territory at three points in Ladakh and Sikkim. The transgressions are reportedly in **Galwan River Valley** and **Pangong Tso Lake Area in Ladakh**.

Reports of Chinese Army moving thousands of troops in Galwan Valley and Pangong Tso Lake Area (Ladakh) are shocking and audacious attempt on our "territorial integrity".

Security experts and Army veterans are seeing the Chinese transgressions into the Galwan River Valley as an attempt to threaten the "Darbuk-Shyok-DBO Road" which is vital to servicing Indian troops in Sub-Sector North and close to the Karakoram pass.

If these reports are true, the Modi Government must answer:

1. Have Chinese troops occupied Indian Territory in the "Galwan River Valley", "Pangong Tso Lake" in Ladakh?

   Have they crossed into Indian Territory even beyond China's own 'Claim Line', pitched hundreds of tents, constructed concrete structures and built a few kilometres of road along the LAC in Galwan River Valley as also on the north bank of "Pangong Tso Lake"?

2. Is it correct that Chinese troops have occupied the "Finger Heights" near Pangong Tso Lake?

3. Do the Chinese transgressions into Galwan River Valley threaten the operation of "Darbuk-Shyok-DBO Road" vital to servicing Indian troops in Sub-Sector North and Karakoram pass?

4. What steps have the Modi Government taken to resolve this all important issue of "National Security and Territorial Integrity", including strategic preparations?

5. Why has the Modi Government not taken the Nation into confidence vis-à-vis the actual position on the ground?

While Government has briefly commented upon resolving the crisis diplomatically, Modi Government must take all political parties and the country into confidence on restoring the status quo ante and protecting India's territorial integrity.

प्रेस विज्ञप्ति **01 जून, 2020**

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बयान

''चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर क्यों मौन बैठी है मोदी सरकार?''

भारत की 'सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता' से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।

चीनी सेना द्वारा लद्दाख और सिक्किम में तीन स्थानों पर भारतीय सीमा में घुसपैठ समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हुई है। तथाकथित तौर से ये घुसपैठ लद्दाख में गलवान नदी वैली और पैंगोंग सो झील के इलाके में हुई है।

खबरों की मानें तो चीनी सेना के हजारों सैनिकों ने गलवान वैली और पैंगोंग सो लेक एरिया (लद्दाख) में घुसपैठ कर हमारी 'भूभागीय अखंडता' पर अतिक्रमण का दुस्साहस किया है।

सुरक्षा विशेषज्ञों और सेना के जानकारों की मानें तो गलवान नदी वैली में चीन की घुसपैठ से 'डर्बुक-श्योक-डीबीओ रोड' को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके में तथा काराकोरम दर्रा के नज़दीक भारतीय सेना को रसद व सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

सामरिक विशेषज्ञों व देश की इन चिंताओं बारे मोदी सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट कर जवाब देना चाहिए:

1. क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में 'गलवान नदी वैली' और 'पैंगोंग सो लेक' के हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है?

   क्या उन्होंने चीन द्वारा स्वीकारित 'सीमा रेखा' को लांघकर गलवान नदी वैली में सैकड़ों टेंट, कान्क्रीट के ढांचे व लाईन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार कई किलोमीटर सड़क बना ली है व इसी प्रकार से 'पैंगोंग सो लेक' के उत्तरी तट पर भी क्या सड़क निर्माण किया है?

2. क्या यह सही है पैंगोंग सो लेक के पास 'फिंगर हाईट्स' फिलहाल चीनी सेना के कब्जे में है?

3. क्या गलवान नदी वैली में चीनी घुसपैठ से 'डरबुक-श्योक-डीबीओ' रोड़ पर संचालन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके में तथा काराकोरम दर्रा के नज़दीक भारतीय सेना को रसद व सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है?

4. 'राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता' की इन महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाने के लिए मोदी सरकार ने क्या रणनीतिक तैयारियां की हैं और क्या कारगर कदम उठाए हैं?

5. मोदी सरकार ने लाईन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात पर देश व देश लोगों के साथ हालात का विवरण साझा क्यों नहीं किया?

यद्यपि मोदी सरकार ने इस संकट को कूटनीतिक तौर पर सुलझाने बारे बयान दिया है, लेकिन मोदी सरकार को भारत की भूभागीय अखंडता की रक्षा करने तथा भारत-चीन सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल करने बारे देश के नागरिकों एवं सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए।